बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!
सक्षम भारत
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित
www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com
Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI
● वर्ष: 23 ● अंक: 231 ● नई दिल्ली ● सोमवार 15 सितम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें
E-mail : rmsdp@hotmail.com
अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

सेहत से ऐसा खिलवाड़! 7600 लीटर मिलावटी घी बनाने वाली फैक्ट्री का दिल्ली पुलिस ने किया पर्दाफाश

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने राजधानी दिल्ली में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले एक बड़े बैंक का पर्दाफाश किया है. बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में चल रहे नकली घी बनाने के धंधे पर छापा मारते हुए दिल्ली पुलिस ने करीब 7600 लीटर अवतार ब्रांड का मिलावटी घी और 900 लीटर वनस्पति और ग्राउंडनट ऑयल बरामद किया है. इस घी को बाजार में शुद्ध बताकर बेचा जाना था. दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि बवाना के सेक्टर दो में स्थित फैक्ट्री में मिलावटी घी बनाया जा रहा है. दिल्ली पुलिस ने सूचना को गंभीरता से लेते हुए एक टीम का गठन किया. वहीं, दिल्ली पुलिस ने फूड सिक्यूरिटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी अपनी टीम में शामिल किया.

हरिद्वार से अस्थि विसर्जन कर लौट रहा परिवार भीषण हादसे का शिकार, 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत

जयपुर। राजस्थान में रविवार को एक परिवार भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया. इस हादसे में सात लोगों की जान चली गई, जिसमें से दो बच्चे और दो महिलाएं थीं. यह हादसा जयपुर के पास शिवदासपुरा इलाके में रिंग रोड पर हुआ. तेज रफ्तार कार सड़क पर से नीचे एक अंडरपास के पास जा गिरी. हादसा इतना भीषण था कि कार के परखचे उड़ गए. कार में सवार लोग अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार गए थे और लौटते वक्त यह हादसा हुआ. सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए. जानकारी के मुताबिक, कालू राम अपने पिता की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए परिवार के साथ हरिद्वार गए थे. लौटते वक्त उनकी कार अनियंत्रित होकर के सड़क से कुछ फुट नीचे एक अंडरपास के पास जा गिरी. जहां पर पानी भरा हुआ था. रिंग रोड पर हुए इस भीषण सड़क हादसे में कार में सवार सात लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में दो बच्चे और दो महिलाएं भी शामिल हैं. सभी मृतक केकड़ी और वाटिका इलाके के रहने वाले थे. मृतकों में कालू राम और उनकी पत्नी सीमा के साथ ही उनके 14 महीने के बेटे रुद्र की मौत हो गई. साथ ही रामराज और उनकी पत्नी मधु भी मृतकों में शामिल हैं. वहीं इस हादसे ने रोहित और उनके 3 साल के बेटे गजराज को भी छीन लिया. दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी से कार को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकलवाया. मृतकों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है. वहीं मृतकों के परिजनों को सूचित किया गया है.

सपा सांसद आदित्य यादव का सरकार पर निशाना, कहा- देश में बढ़ रही है बेरोजगारी और महंगाई

बदायूं। बदायूं में तीन दिवसीय दौरे पर शहर पहुंचे सपा सांसद आदित्य यादव ने रविवार को अपने आवास पर प्रेसवार्ता कर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि नेपाल में फंसे बदायूं संसदीय क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए उन्होंने सरकार को पत्र लिखा था, जिसके बाद सभी लोग सकुशल घर लौट आए। सांसद ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, टीईटी पर शिक्षकों का विरोध और बाढ़ की गंभीर स्थिति जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि विकास कार्य तो हुए ही नहीं, बल्कि सरकार में शामिल लोग खुद स्वीकार कर रहे हैं कि किस तरह घूस और भ्रष्टाचार के नाम पर पैसा लिया जाता है। उपराष्ट्रपति चुनाव पर आदित्य यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट रहा। भले ही चुनाव हारे हों, लेकिन यह संदेश पूरे देश में गया है कि गठबंधन भ्रष्ट और बेईमान सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। जीएसटी दरों में कटौती होने पर सांसद ने कहा कि विपक्ष लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था। उन्होंने सवाल उठाया कि अब तक जनता से जो लूटा गया उसकी भरपाई कौन करेगा।

प्रधानमंत्री पर निशाना साधा

मणिपुर मुद्दे पर सपा सांसद ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पास हर जगह जाने का समय था, लेकिन मणिपुर जाने का समय नहीं था। आज जब हालात बिगड़ गए तो प्रधानमंत्री राजनीतिक फायदा उठाने वहां पहुंच रहे हैं। सांसद ने विपक्ष पर विदेशी ताकतों के आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश और केंद्र दोनों जगह भाजपा की सरकार है, तो जांच क्यों नहीं कराई जाती। विजन 2047 कार्यक्रम पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2047 का रोडमैप दिखाने से पहले जनता को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। बाढ़ में लोग फंसे रहते हैं, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में यह विजन जनता को गुमराह करने वाला है।

एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को ईडी ने भेजा समन

नई दिल्ली।

बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए समन जारी किया है.
उर्वशी रौतेला को 16 सितंबर को ईडी के दिल्ली मुख्यालय में पेश होना होगा, जबकि टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को 15 सितंबर को पूछताछ के आना होगा. टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती बंगला फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस भी हैं. ऐसे में दोनों फिल्म एक्ट्रेस को पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच के अधिकारियों के सामने पेश होना होगा. मिली जानकारी के अनुसार उर्वशी रौतेला और मिमी चक्रवर्ती को अवैध बेटिंग ऐप 1&Bet के मामले में ईडी ने समन जारी किया है. इस मामले में ईडी ने बीते दिनों कई एक्ट्रेस और क्रिकेटर्स से पूछताछ की है. एक्ट्रेस उर्वशी

रौतेला को 16 सितम्बर को ईडी के दिल्ली मुख्यालय में पेश होना होगा. बताते चले कि एजेंसी क्रिकेटर सुरेश रैना सहित कई हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों से इस प्लेटफॉर्म से उनके कथित संबंधों की जाँच कर रही है. दूसरी ओर टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को 15 सितम्बर को ईडी के दिल्ली मुख्यालय में पेश होना होगा. ईडी मिमी चक्रवर्ती से 1&Bet के साथ उनकी कथित संलिप्तता के बारे में पूछताछ कर सकता है. 1&Bet एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी का आरोप है.

सीएम ममता बनर्जी ने हिन्दी दिवस पर दी बधाई

कोलकाता। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस अवसर पर रविवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषी समुदाय को बधाई दी और राज्य सरकार द्वारा उनके विकास के लिए किए गए प्रयासों के बारे में बताया. सीएम ममता ने कहा कि उनकी सरकार सभी भाषाओं का सम्मान करती है. मुख्यमंत्री ने राज्य में हिंदी भाषी लोगों के कल्याण के लिए अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों का भी जिक्र किया, जिसमें उन क्षेत्रों में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देना भी शामिल है जहां 10 प्रतिशत आबादी हिंदी बोलती है. ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, आज हिन्दी दिवस है. इस अवसर पर सभी हिन्दी भाषी भाई-बहनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं. प्रत्येक वर्ष हम श्रद्धा के साथ हिन्दी दिवस मनाते हैं. हम सभी भाषाओं के प्रति श्रद्धावान हैं. इस संदर्भ में कहूं तो वर्ष 2011 के बाद से राज्य में हिन्दी भाषी लोगों के विकास के लिए हमने कई अहम कदम उठाए हैं.

बिहार में राजगन की जीत करें सुनिश्चित : नड्डा

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव तैयारियों की संगठनात्मक समीक्षा करने पटना पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी पार्टी के नेताओं से अपील की कि वे व्यक्तिगत अहंकार को त्याग कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की जीत को सर्वोपरि रखें। राजकीय अतिथिशाला में नड्डा ने बिहार भाजपा के शीर्ष नेताओं, नीतीश सरकार में भाजपा कोटे के मंत्रियों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों, विधानसभावार सम्मेलन आदि बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने सामाजिक पकड़ मजबूत बनाने के साथ ही राजग के बूथ स्तर तक के

कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाने पर बल दिया। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बी एल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उपमुख्यमंत्री द्वय सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा, पूर्व भाजपा अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय चुनाव समिति एवं कोर ग्रुप के सचिव प्रेम रंजन पटेल तथा अन्य वरिष्ठ नेता सम्मिलित हुए। नड्डा ने विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का नया नामकरण किया। उन्होंने राजद का मतलब समझाते हुए कहा कि 'र' का मतलब 'रंगदारी', 'ज' का मतलब 'जंगलराज' और 'द' का मतलब 'दादागिरी' है। उन्होंने कहा कि आज मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के लोग विकास देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा,'' 2005 से पहले बिहार की स्थिति क्या थी और आज क्या है। 2005 से पहले तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार और सत्ता समर्थित अपराध की राजनीति थी।

विकसित भारत 2047 के निर्माण में महिलाओं की भूमिका अहम, महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में बोले ओम बिरला

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को कहा कि देश की महिलाएं अपने नेतृत्व और दृष्टिकोण से विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने यह बात संसद और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिला सशक्तिकरण समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन में कही। इस दौरान ओम बिरला ने कहा कि महिलाएं आज देश के विकास में नई सोच के साथ योगदान दे रही हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत कर रही हैं। ओम बिरला ने आगे संविधान निर्माण में भी महिलाओं की भूमिका पर

जोर दिया। उन्होंने कहा कि संविधान सभा में करीब 15 महिला सदस्य थीं, जिन्होंने संविधान को आकार देने में अहम योगदान दिया। उन्होंने यह भी बताया कि दुनिया के कई देशों के विपरीत, भारत ने शुरुआत से ही महिलाओं को वोट देने, समानता और न्याय का अधिकार दिया। इसके साथ ही बिरला ने यह भी कहा कि आज महिलाएं वित्त, तकनीक और खेल जैसे क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने यह भी गर्व के साथ कहा कि आज देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू हैं, जो महिला सशक्तिकरण का प्रतीक हैं। बता दें कि केंद्र सरकार के अनुसार, विकसित भारत 2047 का लक्ष्य स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत को एक विकसित देश बनाना है।

बसपा को फिर खड़ा करने की तैयारी

अनिल जैन

लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में आधे-अधूरे राममंदिर का धूमधड़ाके से उद्घाटन हुआ था लेकिन भाजपा को चुनाव में उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बावजूद वह मंदिरों का मुद्दा छोड़ने को राजी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मथुरा का मुद्दा जोर पकड़ेगा। कई स्तर पर इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शुरुआत शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे के लिए अदालत में की गई अपील से हुई थी। लेकिन अब बात उससे आगे बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि यह मुद्दा जमीनी स्तर पर जोर पकड़ने लगा है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों किसी न किसी तरीके से इसका संकेत दे रहे हैं। पिछले दिनों बागेश्वर धाम के विवादित धीरेंद्र शास्त्री ने मथुरा में जाकर कई बातें कहीं। उसने कहा कि भगवान राम विराजमान हो गए हैं और अब कृष्ण कन्हैया भी विराजेंगे। उसने मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह विवाद की ओर इशारा किया। इसके बाद उसने कहा कि धर्मस्थलों पर राष्ट्रीय गीत जैसे वंदेमातरम आदि बजना चाहिए इससे पता चलेगा कि राष्ट्र के प्रति किसके मन में कितनी श्रद्धा है। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम कर तारीफ भी की। उसकी इन बातों राजनीतिक अर्थ इसलिए निकाला जाएगा क्योंकि भाजपा ने उसके इंटरव्यू का वीडियो अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया है। धीरेंद्र शास्त्री सात नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से मथुरा-वृंदावन तक की पद यात्रा पर निकलेगा। उसके साथ कई साधु संत भी यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा का मकसद मथुरा के मुद्दे का प्रचार करना है। इस यात्रा से जो माहौल बनेगा उसका असर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दिखेगा।

जांबाज सैनिकों की पहचान उजागर होना खतरनाक

भारतीय सेना के जवानों ने पिछले दिनों 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया और महादेव पहाड़ियों पर तीन खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया। सरकार ने बताया कि ये तीनों आतंकवादी पाकिस्तानी थे। इससे पहले भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। उसमें भी एक सौ से ज्यादा आतंकवादी मारे जाने का दावा किया गया था। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव में शामिल भारत के जांबाज सैनिकों को पिछले दिनों सम्मानित किया है। सभी टेलीविजन चैनलों पर इस सम्मान समारोह का प्रसारण हुआ और अखबारों में तस्वीरें छपीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सैनिकों को सम्मानित किया। यह अजीब-ओ-गरीब काम सिर्फ भारत में ही हो सकता है। दुनिया के दूसरे सभी देशों में इस तरह के सैन्य ऑपरेशन होते हैं तो सैनिकों की पहचान गोपनीय रखी जाती है। ओसामा बिन लादेन को मारने के अभियान में शामिल अमेरिकी नेवी के सैनिकों की पहचान एक दशक से ज्यादा समय तक गोपनीय रखी गई। ऑपरेशन के दौरान सभी सैनिकों ने मास्क पहना हुआ था। इजराइल की खुफिया एजेंसी जो कार्रवाई करती है, उसमें भी सबकी पहचान गोपनीय रहती है। लेकिन भारत में खूंखार आतंकवादियों को मारने वालों की पहचान सार्वजनिक कर दी जाती है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए उनको सम्मानित करने का लोभ भारत के नेता रोक नहीं पाते हैं। अगर सम्मानित ही करना है तो यह काम बंद कमरे में होना चाहिए। इस तरह पहचान सार्वजनिक करने से ऐसे बड़े ऑपरेशन में शामिल सैनिकों और उनके परिजनों की जान खतरे में पड़ती है।

अमरिंदर सिंह पर ईडी की तलवार

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह काफी समय से बीमार है और परिवार के सारे सदस्य चुनाव हार कर पस्त पड़े हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि उनका परिवार कांग्रेस में वापसी करना चाहता है। कांग्रेस छोड़ने से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने पहले अपनी पार्टी बनाई और बाद में उसका विलय भाजपा में कर दिया। लेकिन न उनकी पार्टी सफल हुई और न भाजपा के साथ जाने पर कुछ हासिल हुआ। उनके साथ-साथ कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में गए सुनील जाखड़ प्रदेश अध्यक्ष तो बने लेकिन लॉटरी खुली कांग्रेस छोड़ने वाले दूसरे नेता रवनीत सिंह बिट्टू की। वे लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बनाए गए और राज्यसभा में भेजे गए। बहरहाल, कांग्रेस में वापस लौटने की चर्चाओं के बीच अमरिंदर सिंह को बड़ा झटका लगा है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते उनकी एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने आयकर विभाग की फाइलें ईडी को नहीं देने की अपील की थी। ये फाइलें विदेश में संपत्ति से जुड़ी हैं, जो फ्रांस की सरकार ने आयकर विभाग को दी हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि ईडी उन फाइलों की जांच कर सकती है। इसका मतलब है कि कैप्टन अमरिंदर और उनके बेटे रणइंदर सिंह की विदेश में स्थित संपत्तियों से जुड़ी फाइल ईडी देख सकेगी और उसकी जांच कर सकेगी। बताया जा रहा है कि इन फाइलों में दुबई और स्विट्जरलैंड में निवेश की जानकारी है।

कांग्रेस कार्यालय अटैच करेगी ईडी

आजाद भारत के इतिहास में संभवतः पहली बार होगा कि किसी पार्टी का कार्यालय कोई केंद्रीय एजेंसी अटैच कर लेगी। हालांकि पार्टियों को आरोपी बनाने की शुरुआत हो गई है। आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जा चुका है और केरल में सीपीएम को भी आरोपी बनाया जा चुका है। लेकिन पार्टी कार्यालय अटैच करने का नोटिस मिला है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को उसका सुकमा जिला कार्यालय अटैच करने का नोटिस मिला है। ईडी की ओर से नोटिस के साथ-साथ कई दस्तावेज पार्टी कार्यालय में जाकर दिए गए हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है। इस जांच में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित उनके प्रशासन के अनेक अधिकारियों और नेताओं के नाम हैं। इसी सिलसिले में ईडी ने सुकमा कार्यालय अटैच करने की अपील पीएमएलए ट्रिब्यूनल में की थी। पीएमएलए ट्रिब्यूनल के सामने कांग्रेस की ओर से कहा गया कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस को जानकारी देने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों ने सुकमा में कांग्रेस कार्यालय में जाकर नोटिस और दूसरे कागजात दिए। अब तक आरोपियों की संपत्ति अटैच होते सुना गया था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक राष्ट्रीय पार्टी का कार्यालय अटैच होगा।

बसपा को फिर खड़ा करने की तैयारी

बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती फिर से पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। लगातार दो चुनाव यानी 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से फेल होने के बाद पार्टी पस्त पड़ी है। पिछले चुनाव में तो बसपा सिर्फ नौ फीसदी वोट की पार्टी बन कर रह गई। यह कहा जाने लगा कि बसपा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऊपर से चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी बना कर बसपा के वोट आधार और कांशीराम की विरासत पर दावा कर दिया। वे अपनी पार्टी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी जीत गए, जबकि बसपा एक भी सीट नहीं जीत सकी। अब मायावती ने पार्टी को एकजुट करना शुरू किया है। पार्टी की ताकत का लंबे अरसे बाद नौ अक्टूबर को प्रदर्शन होने जा रहा है। नौ अक्टूबर को कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में बसपा की ओर से बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है। आकाश के ससुर और पूर्व राज्यसभा सांसद सिद्धार्थ अशोक की भी पार्टी में वापसी हो गई है। मायावती बिहार चुनाव में भी पूरी ताकत से उतरने की घोषणा की है। हालांकि बिहार की तैयारी के बारे में कहा जा रहा है कि वहां भी वे भाजपा का काम करेंगी क्योंकि भाजपा को लग रहा है कि वहां दलित का जो वोट राष्ट्रीय जनता दल की ओर जा रहा है, उसे बसपा तोड़ सकती है। खैर ऐसी बातें हर बार होती हैं, लेकिन फिलहाल यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बसपा दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो पाती है या नहीं।

सम्पादकीय...

क्या भाजपा को मिलेगी पहली महिला अध्यक्ष?

अपना चाल, चरित्र व चेहरा बदलने की कवायद में यह पार्टी अपने अभ्युदय काल से ही जुटी है, नई सियासत की पैरोकारी और नए मिथक गढ़ने की बाजीगरी में भी इस भगवा पार्टी का कोई सानी नहीं। खास कर 2014 के बाद से ही पार्टी में कई मान्य परंपराओं को धत्ता बता कर कई बड़े फैसले लिए गए हैं, क्या आने वाला वक्त भी एक ऐसा ही नया अध्याय लिखने की तैयारियों में है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या भाजपा की अगली राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती हैं? नहीं तो क्या वजह है कि नई दिल्ली स्थित उनके सरकारी बंगले 15 सफदरजंग रोड पर सीपीडब्ल्यूडी न सिर्फ तोड़-फोड़ कर नई आधारभूत संरचनाएं तैयार कर रहा है, मीटिंग के लिए बड़े हॉल बनाए जा रहे हैं, कई पोर्टा कैबिन लगाए जा रहे हैं, बंगले की साज-सज्जा भी बदली जा रही है, आगंतुकों के लिए बड़े वेटिंग रूम तैयार किए जा रहे हैं। जब इस बारे में वित्त मंत्री से संबद्ध एक अधिकारी से कुछ जानने की चेष्टा हुई तो उन्होंने गोल-गोल घुमाते हुए कहा कि 'चूंकि माननीय मंत्री जी को अब घर पर ही बहुत सारी विभागीय मीटिंग्स लेनी पड़ जाती हैं सो, उसे देखते हुए ही नए निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं।' पर यह बात सहजता से गले नहीं उतरती क्योंकि यह कोई अबूझ पहेली नहीं रह गई है कि आखिरकार माननीया मंत्री जी का मंत्रालय चलता कहां से है? इसे चलाता कौन है? चलो एक पल को यह बात मान भी ली जाए कि मंत्री महोदया पर शायद 'वर्कलोड' बढ़ गया हो, पर पिछले तीन महीनों से नियम से उन्हें एक गढ़वाली हिंदी टीचर हिंदी सिखाने क्यों आ रहा है? अब मंत्रालय का कामकाज भी कितना हिंदी में होता है यह सबको पता है। हालिया निर्वाचित हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की तरह निर्मला भी तमिलनाडु से ही आती हैं, यानी अगर भाजपा इनको अपना अगला अध्यक्ष चुनती है तो एक तीर से कई निशाने साधे जा सकते हैं। मसलन, देशभर की महिला मतदाताओं के बीच एक सकारात्मक संदेश दिया जा सकता है, दक्षिण के राज्यों में कमल के प्रस्फुटन को उचित माहौल मिल सकता है। और भाजपा को पहली महिला अध्यक्ष देने का श्रेय पार्टी व पार्टी से बाहर मोदी जी को तो मिलेगा ही। आमतौर पर स्वयंसेवक संघ एक संगठन के तौर पर इस कदर परिपक्व व अनुशासित है कि यहां शीर्ष में संघर्ष, टकराव या टंकार की खबरें कभी सतह पर ही नहीं आ पातीं। पर पिछले दिनों जब संघ के नंबर दो दत्तात्रेय होसबोले संघ की जोधपुर की एक सभा में अचानक से अस्वस्थ हो गए, उनका बीपी डाउन हो गया और उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाना पड़ा तो इसके तुरंत बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत के बेहद करीबी माने जाने वाले सुनील आंबेकर ने दत्तात्रेय के स्वास्थ्य की ब्रीफिंग देने के लिए, बकायदा एक प्रेस कांफ्रेंस आहूत कर दी, जिस कांफ्रेंस में पत्रकारों को दत्तात्रेय के स्वास्थ्य के बारे में ताजा अपडेट दिया गया। यह कांफ्रेंस संघ के नजरिए से भी अजूबा थी, संघ एक स्वयंसेवी या स्वायत्त संस्था है और इसके पदाधिकारी होसबोले भी किसी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति नहीं कि उनके लिए कोई 'हेल्थ बुलेटिन' जारी करने की जरूरत आन पड़े।

कहते हैं इस बात से स्वयं होसबोले हैरत में थे कि आखिरकार किसके कहने पर सुनील आंबेकर की ओर से यह धृष्टता हुई। दरअसल, पिछले काफी समय से संघ समर्थकों व सोशल मीडिया में यह सुगबुगाहट उभर रही थी कि इन कुछ दिनों में जब संघ प्रमुख मोहन भागवत भी 75 वर्ष के हो रहे हैं तो क्या वह अपने उत्तराधिकारी के लिए अपनी गद्दी खाली कर देंगे? जब सरसंघचालक पद के लिए उम्र कोई बाधक नहीं, पर चूंकि स्वयं भागवत कई मौकों पर कह चुके हैं कि संघ को अपने नए अवतार में नई पीढ़ी तक अपनी पहुंच बढ़ानी होगी, उसे अपने अप्रोच में भी ज्यादा मॉडर्न होना होगा। भागवत को करीब से जानने वाले लोगों का दावा है कि वह संघ का शीर्ष नेतृत्व भी अपने बाद किसी युवा हाथों में सौंपने के पक्षधर हैं, उनके मन में है कि संघ का नया नेतृत्व वह संभाले जो 55-60 साल का व्यक्ति हो जो अगले एक दशक तक सफलतापूर्वक इसका नेतृत्व कर सके, इससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ सके। चर्चा है कि अगर मौजूदा हालात में भागवत अपनी गद्दी छोड़ते हैं तो उनके स्वाभाविक उत्तराधिकारी संघ के नंबर दो इसके सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ही हैं। पर होसबोले की उम्र भी कोई 70 साल के आस-पास की है जो भागवत के युवा नेतृत्व के ब्योरे पर फिट नहीं बैठती है। वैसे भी दत्तात्रेय की किसी से इस कदर नजदीकियां भागवत करीबियों को नहीं भाती हैं, सो आंबेकर की प्रेस कांफ्रेंस का एक पहलू यह भी हो सकता है कि दत्तात्रेय जी देखो स्वास्थ्य के ग्राउंड पर अब उतने फिट नहीं रह गए हैं। सियासत अगर अनिश्चितताओं की एक अलिखित इबारत है तो इसे आहटों व दस्तकों में ही बूझा जा सकता है, नहीं तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि भाजपा व मोदी विरोध की सतत् अलख जगाने वाली केजरीवाल की पार्टी आप अचानक से कमल के मोहपाश में जकड़ने लगी है। अगर सिर्फ ताजा-ताजा संपन्न हुए उपराष्ट्रपति चुनाव का ही हवाला दिया जाए तो तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी के उस बयान पर जरूर गौर फरमाया जाए जिसमें वे क्रॉस वोटिंग के लिए आप सांसदों की ओर इशारा करते हुए दिखे।

सूत्रों का दावा है कि भविष्य की राजनीति को लेकर भाजपा व आप के दरम्यान एक गुप्त समझौता हुआ है जिसके तहत इन बातों पर सहमति बनी है कि आप पंजाब के अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए एक माकूल माहौल तैयार करेगी यानी एक तरह से भाजपा को पंजाब की सरजमीं पर पैर जमाने में परोक्ष-अपरोक्ष तौर पर आप पूरा सहयोग देगी, बदले में आप नेताओं मसलन, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया व सत्येंद्र जैन पर केंद्रीय जांच एजेंसियां अपना शिकंजा किंचित ढीला कर देंगी, उन्हें बच निकलने के रास्ते भी मुहैया कराए जा सकते हैं। इसके बदले आप भाजपा की 'बी टीम' की तरह चुनावी मैदान में हाथ आजमाएगी, जैसा रोल वह इन बिहार चुनावों में अदा कर रही है, आप ने साफ कर दिया है कि वह बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी यानी यह एक तरह से एनडीए गठबंधन को ही अपरोक्ष तौर पर फायदा पहुंचाने का एक उपक्रम साबित हो सकता है।

नेपाल की नई सरकार

नेपाल की सड़कों पर इसी सप्ताह में पिछले दिनों हुए दो दिन के तांडव के बाद जिस प्रकार लोकतन्त्र बहाल हुआ है उसमें इस देश की सेना की प्रमुख भूमिका रही है क्योंकि सेना ने ही विध्वंस के बाद प्रशासन की कमान संभाली थी और लोगों से शान्ति व अनुशासन बनाये रखने की अपील की थी। सेना ने अराजक परिस्थितियों पर जिस प्रकार नियन्त्रण किया उससे नेपाल की आन्तरिक शक्ति का परिचय भी मिलता है और इस देश को बंगलादेश से अलग खड़ा करता है। नेपाली सेना भी लोकतन्त्र के लिए समर्पित लगती है क्योंकि उसने बहुत जल्दी ही इस देश की पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्रीमती सुशीला कार्की को प्रधानमन्त्री पद संभालने के लिए मना लिया। नेपाल में संविधान लागू है हालांकि यहां की संसद को नई प्रधानमन्त्री ने भंग कर दिया है और छह महीने के भीतर नये चुनाव कराने का आश्वासन दिया है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडयाल द्वारा ही की गई है। नेपाल की ताजा परिस्थिति पर भारत ने सन्तोष व्यक्त किया है और नई सरकार के साथ सहयोग करने का भी वचन दिया है। एक शान्त व स्थिर और विकसित नेपाल सर्वदा भारत के हित में है क्योंकि भारत ने इसके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आजादी के बाद से ही भारत-नेपाल के सम्बन्ध बहुत दोस्ताना ही नहीं रहे बल्कि इससे भी बढ़कर दो भाइयों के समान रहे हैं। इन सम्बन्धों में खटास पैदा करने का प्रयास हालांकि नेपाल के कम्युनिस्टों ने किया मगर इसके लोगों की सहृदयता की वजह से वे इसमें सफल नहीं हो सके और न ही कभी भविष्य में भी सफल हो सकते हैं क्योंकि दोनों देशों के बीच रोटी-बेटी के रिश्ते हैं। कार्की सरकार का भी यह दायित्व बनता है कि वह इन संजीदा सम्बन्धों को हमेशा संज्ञान में रखे। उन्हें नेपाल में लोकतन्त्र की पूरी बहाली की जिम्मेदारी सौंपी गई है अतः बहुत जरूरी है कि वह नेपाल के बहुआयामी हितों को सर्वोपरि रखें। नेपाली जनता भी जानती है कि भारत ने इस देश में लोकतन्त्र बहाली के लिए यहां के नागरिकों की इच्छा का पूरा सम्मान किया था और 2008 में राजशाही के खिलाफ उपने विद्रोह से स्वयं को दूर रखते हुए घोषणा की थी कि भारत वही चाहता है जो नेपाल की जनता चाहती है। 2008 में भारत में मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार थी और इसके विदेश मन्त्री भारत रत्न स्व. प्रणव मुखर्जी थे। जब 2008 में राजशाही के खिलाफ नेपाल की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हो रहे थे तो उस समय प्रधानमन्त्री डॉ. मनमोहन सिंह विदेश यात्रा पर थे और उनकी अनुपस्थिति में सरकार का कामकाज वरिष्ठतम होने से प्रणव दा ही देख रहे थे। उन्हें जब नेपाल के बारे में भारत की चिन्ता व्यक्त करने के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ कहा कि भारत वही चाहता है जो नेपाल की जनता चाहती है क्योंकि किसी भी देश की जनता का ही यह विशेषाधिकार होता है कि वह अपनी मनपसन्द की सरकार का गठन करे। अतः भारत की स्थिति आज भी साफ है और वह इस देश की जनता की इच्छा का सम्मान करता है।

नई प्रधानमन्त्री श्रीमती कार्की के सामने लक्ष्य स्पष्ट है कि संसद के भंग होने के बाद उन्हें लोगों की इच्छा के अनुसार नई सरकार का गठन संविधानतः करना है। नेपाल में संविधान लागू है और इसी के अनुसार अगले छह महीनों के दौरान चुनाव होने हैं जिनमें इस देश के विभिन्न राजनीतिक दल भाग लेंगे। खबरों के अनुसार श्रीमती कार्की अपने मन्त्रिमंडल में श्री कुलमान घीसिंग को भी ऊर्जा मन्त्री नियुक्त करेंगी और कुछ अन्य गैर राजनीतिक व्यक्तियों को भी लेंगी जिससे इन छह महीनों में नेपाल का शासन चुस्त-दुरुस्त हो सके। हालांकि उनकी सरकार अन्तरिम सरकार होगी मगर इसका दायित्व इससे कम नहीं होगा क्योंकि उन्हें पटरी से उतरे नेपाल को पुनः पटरी पर लाना होगा और स्थितियां सामान्य व लोकतन्त्र मूलक बनानी होंगी। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह होगी कि नेपाल में हिंसा पुनः किसी भी तरह न लौटे। क्योंकि केवल दो दिन की हिंसा में ही नेपाल के सारे लोकतान्त्रिक संस्थान फूंक डाले गये जिनमें संसद तक शामिल थी। इस हिंसा के दौरान जिस प्रकार पी.के. शर्मा ओली सरकार के मन्त्रियों को सड़कों पर पीटा गया और उनके घर आग के हवाले किये गये उससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि जनता में राजनीतिज्ञों के प्रति कितना गुस्सा है। बेशक युवा पीढ़ी का हिंसा मूलक यह तांडव किसी विदेशी साजिश के होने से इन्कार भी नहीं कर सकता है मगर इतना तो तय है कि नेपाली जनता के बीच राजनीतिज्ञों की विश्वसनीयता शून्य के स्तर पर पहुंच गई है। देश में राजनैतिक व आर्थिक भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा पीढ़ी के गुस्से को जायज तो ठहराया जा सकता है मगर इसके विरुद्ध किये गये ऐसे हिंसक प्रदर्शन का समर्थन भी नहीं किया जा सकता जिसमें अपना ही घर फूंक कर तमाशा बनना पड़े लेकिन नेपाल यदि पटरी पर लौट रहा है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए और कार्की सरकार के साथ नेपाल की युवा पीढ़ी को भी सहयोग करना चाहिए। क्योंकि नेपाल में बदलाव हिंसा के माध्यम से नहीं बल्कि संविधान के रास्ते से ही आयेगा जिसकी व्यवस्था यहां की सेना के सहयोग से की गई है। मगर श्रीमती कार्की ने प्रधानमन्त्री पद संभालने से पूर्व ही कह दिया था कि वह नेपाल में उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार की जांच जरूर करायेंगी जिसकी उन्हें छूट मिलनी चाहिए। इससे नेपाल की युवा पीढ़ी को भी आश्वस्त होना चाहिए कि उसकी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग अनसुनी नहीं जायेगी और अन्तरिम सरकार ही इस दिशा में निर्णायक कार्रवाई करेगी।

मोदी का जीएसटी सुधार

3 सितंबर 2025, भारत की आर्थिक यात्रा में एक ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाएगा। मोदी सरकार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जनता के कल्याण और राष्ट्र के विकास के लिए उसका संकल्प अटूट है। साहसिक और दूरदर्शी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों की घोषणा कर सरकार ने आम जनता को सच्चा दिवाली उपहार दिया है। जीएसटी परिषद की दिनभर चली बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि अब कर संरचना को दो सरल दरों 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत में बदल दिया जाएगा। सरकार ने दरों में तर्कसंगत बदलाव, व्यापार सुगमता, प्रक्रियागत सुधार और कानूनों में आवश्यक संशोधन पर आधारित 80 पन्नों का विस्तृत प्रेस नोट जारी किया। इन सुधारों का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है - आम आदमी पर बोझ कम करना, घरेलू उद्योगों को मजबूती देना और भारत की आर्थिक नींव को और सुदृढ़ करना। वैश्विक अर्थव्यवस्था जब दबाव झेल रही है, ऐसे समय में मोदी सरकार ने जो कदम उठाया है वह उसकी दूरदर्शिता और साहस का प्रमाण है। यह सुधार एक आत्मविश्वासी और सशक्त भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है। सबसे बड़ा फायदा सीधे घर-घर तक पहुंचेगा। दूध, पनीर और पैकेज्ड भारतीय ब्रेड जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थ अब करमुक्त हो गए हैं। वहीं साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, बैग्स और साइकिल जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं पर कर घटाकर केवल 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका सीधा अर्थ है कि अब आम परिवार की थाली से लेकर उनकी दैनिक जरूरतों तक हर जगह बचत होगी। स्वास्थ्य सेवाओं और बीमा पर लिया गया निर्णय क्रांतिकारी है। 33 जीवन रक्षक दवाओं को पूरी तरह करमुक्त कर दिया गया है। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में प्रयुक्त 3 विशेष दवाओं पर भी अब कोई कर नहीं लगेगा। कई अन्य दवाओं पर कर दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। बीमा के क्षेत्र में भी पहली बार सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा योजनाएं चाहे वे टर्म लाइफ हों, एंडोमेंट हों या यूलिप पूरी तरह जीएसटी मुक्त कर दी गई हैं। इसी तरह सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, परिवार फ्लोटर और वरिष्ठ नागरिक योजनाएं अब शून्य कर के दायरे में हैं। भारत की नई मध्यवर्गीय और युवाओं की पीढ़ी की आकांक्षाएं भी मोदी सरकार ने ध्यान में रखीं। छोटी कारें, मोटरसाइकिलें, टीवी, डिशवॉशर और एयर कंडीशनर जैसी वस्तुओं पर कर दर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। इससे लाखों परिवारों का सपना पूरा होगा और देश में उपभोक्ता मांग भी बढ़ेगी। विशेषज्ञों के अनुसार छोटे वाहनों की बिक्री में इस साल 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी। कृषि क्षेत्र को मिली राहत अप्रत्याशित है। इसका लाभ सीधे किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण भारत में नई ऊर्जा के रूप में मिलेगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को मोदी सरकार ने हमेशा राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी माना है। जीएसटी सुधारों में उनके लिए विशेष ध्यान रखा गया है। कागज, पैकेजिंग, वस्त्र, चमड़ा, लकड़ी और हैंडीक्राफ्ट जैसे क्षेत्रों में कर दर घटाकर केवल 5 प्रतिशत कर दी गई है। खिलौने और खेल सामग्री पर कर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और सस्ते चीनी आयात पर रोक लगेगी।

जीएसटी के 'दीवाली गिफ्ट' की सच्चाई, पूरा गणित समझिए

प्रभात पटनायक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वतंत्रता दिवस भाषण उम्मीद के मुताबिक सफेद झूठों से भरा हुआ था। झूठी शेखी, मिसाल के तौर पर उन्होंने इसका दावा किया कि भाजपा के राज में विनिर्माण के क्षेत्र ने बहुत बड़े डग भरे हैं, जबकि सचाई यह है कि पिछले दस साल में जीडीपी के अनुपात के रूप में विनिर्माण क्षेत्र के हिस्से में भारी गिरावट हुई है और यह 17.5 फीसद से गिरकर, 12.6 फीसद रह गया है, जिस स्तर को 1960 में ही पार किया जा चुका था। इस तरह की गिरावट को अर्थशास्त्री निरुद्योगीकरण की स्थिति कहते हैं। यह वर्तमान प्रधानमंत्री की ही खासियत है कि वह निरुद्योगीकरण की प्रक्रिया को, औद्योगीकरण के क्षेत्र में देश की भारी प्रगति के रूप में चलाने की कोशिश कर सकते हैं। इसी प्रकार उनका स्वतंत्रता दिवस संबोधन में आरएसएस की प्रशंसा करना, सत्य का उपहास करना है। यह एक जानी-मानी सचाई है कि आरएसएस ने न सिर्फ आजादी की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया था, उसके तत्कालीन नेता एमएस गोलवालकर आजादी मिलने के बाद भी यह मानते थे कि यह देश अपने बल बूते पर चीजों को नहीं संभाल पाएगा और अंग्रेजों को वापस बुलाने जा रहा है कि आकर प्रशासन संभालें। (राम पुनियानी ने इस संबंध में लिखा है।)

मोदी का दीवाली ''उपहार''

बहरहाल, आइए हम उनकी मुख्य आर्थिक घोषणा पर आएं, जिसका संबंध गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) में दी जा रही रियायतों से है। उन्होंने एलान किया है कि जीएसटी के दो स्लैब, 12 तथा 28 फीसद खत्म कर दिए जाएंगे। अब से 12 फीसद के स्लैब से नीचे पड़ने वाले मालों तथा सेवाओं पर 5 फीसद कर लगेगा और अब तक जिन पर 28 फीसद कर लगता था, उन पर 18 फीसद कर लगेगा। बेशक, इस रियायत को दीवाली ''उपहार'' बताना, एक वीभत्स सामंती मानसिकता को दिखाता है। कर लोगों द्वारा भरे जाते हैं। कर राजस्व, जनता के पैसे में से आता है। लोगों द्वारा भरे जाने वाले कर राजस्व में किसी कटौती को सरकार की तरफ से एक ''उपहार'' बताना, जैसे सरकार का राजस्व उसकी निजी आय हो, तर्क का ही सिर के बल खड़ा किया जाना है। यह कुछ-कुछ फ्रांसीसी बोरबोन बादशाह, लुई 14वें की टिप्पणी जैसा है कि, 'राज्य, जो कि मैं हूं।' लेकिन, तर्क के इस तरह के शीर्षासन की हम एनडीए सरकार से उम्मीद ही करते हैं। इस सरकार के कुछ वरिष्ठ नेता अतीत में भारतीय सेना को ''मोदी जी की सेना'' तक कह चुके हैं! आइए, हम देखें कि यह प्रस्तावित ''उपहार'' कुल कितना बड़ा है। ऐसा लगता है कि इस समय 28 फीसद के स्लैब में जीएसटी के कुल राजस्व का सिर्फ 11 फीसद आता है। (देखें, द हिंदू, 16 अगस्त)। इसलिए, इस दर के घटाकर 18 फीसद किए जाने से (हम यह मानकर चल रहे हैं, जो पूरी तरह से तार्किक भी है कि मूल्य संवद्धन जिस पर जीएसटी लगायी जाती है, पहले जितना ही रहेगा) इस राजस्व में 10 फीसद की कमी होगी यानी कुल जीएसटी राजस्व में 1.1 फीसद की कमी होगी। इसी प्रकार, 12 फीसद के स्लैब में कुल जीएसटी राजस्व का 5 फीसद आता है और इस दर के घटाकर 5 फीसद किए जाने पर, इस राजस्व में 7 फीसद की कमी होगी यानी जीएसटी के कुल राजस्व में 0.35 फीसद की कमी होगी। इसलिए, इन दोनों रियायतों को मिलाकर, कुल जीएसटी राजस्व में 1.45 फीसद की कमी होगी। चूंकि 2024-25 में कुल जीएसटी राजस्व 22.08 लाख करोड़ था, मोदी द्वारा घोषित इन रियायतों के जरिए जनता के पक्ष में होने वाला कुल हस्तांतरण फिलहाल 32,016 करोड़ रुपये बैठता है यानी 2024-25 के जीडीपी के आधिकारिक अनुमान के सिर्फ 0.0967 फीसद के बराबर। हम मोटे अनुमान के लिए इसे 0.1 फीसद मान लेते हैं। (बाद में दोबारा गणना करने पर पाया गया कि यह जीडीपी का 0.1 फीसद नहीं 0.6 फीसद रहने जा रहा है और 0.32 लाख करोड़ नहीं 1.95 लाख करोड़ रहने जा रहा है।)

समग्र अर्थव्यवस्था पर कैसे और कितना प्रभाव?

बेशक, सरकारी सूत्र इसकी ओर इशारा करने में लगे हुए हैं कि जनता के लिए इस ''उपहार'' का अर्थव्यवस्था पर कैसा विस्तारकारी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन, इसका कुल मिलाकर आर्थिक विस्तारकारी प्रभाव पड़ना इस पर निर्भर करेगा कि इस ''उपहार'' के लिए वित्त व्यवस्था, कैसे की जाती है।

अगर जनता को दी जाने वाली इस कर रियायत के ही बराबर, सरकारी खर्च में कटौती कर दी जाती है, जिससे राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी नहीं हो, तो इस तरह की रियायत से जो आर्थिक विस्तारकारी प्रभाव पैदा होगा, उसे सरकार के खर्च में कटौती का संकुचनकारी प्रभाव काट देगा और कुल मिलाकर शून्य विस्तारकारी प्रभाव होगा। और अगर ये कटौतियां शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा, रोजगार निर्माण तथा इसी प्रकार की गतिविधियों में सरकारी खर्चों में की जाती हैं, तो इन कर रियायतों का जो कल्याण वृद्धिकारी प्रभाव हो सकता है, उसे पूरी तरह से पलट दिया जाएगा। उस स्थिति में ये कर रियायतें न तो आर्थिक वृद्धि बढ़ाने साबित होंगी और न कल्याण बढ़ाने वाली। बहरहाल, मान लीजिए कि मोदी सरकार द्वारा घोषित कर रियायतों की भरपाई के लिए, सरकारी खर्चों में कोई कटौती नहीं की जाती है और इन रियायतों के चलते राजकोषीय घाटे में ही बढ़ोतरी होती है। उस सूरत में भी, अगर हम गुणनकारी या मल्टीप्लायर मान 2 के बराबर मानें तो, जो कि किसी भी तरह से अतार्किक नहीं है क्योंकि ये रियायतें सिर्फ सबसे गरीबों या ग्रामीण आबादी को तो दी नहीं जा रही हैं (जिनके मामले में इससे ज्यादा गुणनकारी मान की अपेक्षा की जा सकती थी) बल्कि ये रियायतें तो सामान्य रूप से जनता को दी जा रही हैं, इससे हमारी सालाना वृद्धि दर में 0.2 फीसद का ही इजाफा हो सकता है, जोकि बहुत ही थोड़ा है। अपने प्रदर्शन के मामले में बहुत बढ़-चढ़कर बातें करने वाली सरकार ही जीडीपी के महज 0.6 फीसद के बराबर की कर रियायतों को ऐसा दीवाली ''उपहार'' बता सकती है, जिसका इस तरह बखान किया जा रहा है।

अर्थव्यवस्था में जान डालने से दूर

अगर सरकार अर्थव्यवस्था में जान डालने के प्रति वाकई गंभीर थी, तो उसे सरकारी खर्च में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करनी चाहिए थी। शुरूआत के तौर पर, मसलन सार्वजनिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य-रक्षा संस्थाओं में खाली पड़े पदों को समुचित रूप से प्रशिक्षित लोगों से (मौजूदा निजाम के पसंदीदा से नहीं) भरा जा सकता था और इस खर्च के लिए वित्त व्यवस्था संपत्ति कर तथा विरासत कर लगाने के जरिए की जा सकती थी। अब इसका इशारा किया जा रहा है कि देश में संपदा की असमानता, अब तक जितना समझा जाता था, उससे कहीं ज्यादा है। पहले अनुमान यह था कि सबसे धनी एक फीसद आबादी के पास देश की संपदा का करीब 40 फीसद हिस्सा है। लेकिन, अमरीका-आधारित संपदा प्रबंधन फर्म, बर्नस्टीन ने अब अपनी एक रिपोर्ट में इसका इशारा किया है कि भारत में सबसे धनी एक फीसद के पास, देश की संपदा का कुल 60 फीसद हिस्सा है।

इस मामले में एकदम सटीक अनुमान लगाना मुश्किल होगा, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि ठीक-ठीक यह आंकड़ा कितना है, यह साफ तौर पर दुनिया के सबसे ऊंचे स्तर पर है। इसके ऊपर से देश में संपदा असमानता और बढ़ती ही जा रही है। इसलिए, आदर्श स्थिति तो यह होती कि अर्थव्यवस्था में जान डालने की योजना इस तरह बनायी जाती, जिससे इसके साथ ही साथ संपदा असमानता की इस लानत पर भी चोट की होती क्योंकि यह लानत तो जनतांत्रिक समाज के मिजाज के बुनियादी तरीके से खिलाफ है। और प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दिवस संबोधन, आर्थिक पुनर्जीवन की ऐसी रणनीति का एलान करने का मौका होना चाहिए था। लेकिन, मोदी सरकार ने ऐसा करने की कोशिश नहीं की है। उसने अर्थव्यवस्था में नयी जान डालने के लिए या जनता को राहत दिलाने के लिए भी, शायद ही कुछ किया है, उल्टे बड़बोलेपन से ''दीवाली उपहार'' देने का दावा किया है! लेकिन, ऐसी सरकार से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, जो सार्वजनिक दिखावे को, कोई ठोस कदम उठाने के मुकाबले ऊपर रखती है।

भागवत की दोमुंही बातें

आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने पिछले ही दिनों यह स्वीकार किया था कि शिक्षा तथा स्वास्थ्य-रक्षा का इतना ज्यादा बाजारीकरण हो गया है और इसके चलते इन्हें इतना ज्यादा महंगा कर दिया गया है कि पहले की स्थिति के विपरीत, वे आम जनता की पहुंच से बाहर हो गए हैं। यह एक महत्वपूर्ण स्वीकृति है, जो निहितार्थतः इस विचार को कबूल किए जाने को दिखाती है कि इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सरकार की ही मुख्य जिम्मेदारी होना चाहिए न कि उनका नव-उदारवादी रणनीति के अनुसार निजीकरण किया जाना चाहिए। बहरहाल, भागवत की स्वीकृति तो सचाई के एक हिस्से को ही कवर करती है। दूसरा हिस्सा है, उन्हीं के कुनबे के बदमाशों तथा अवसरवादियों द्वारा व्यवस्थित तरीके से सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं का नष्ट किया जाना। आरएसएस के प्रति वफादार छात्र उपद्रवी विश्वविद्यालयों में विचारों को लेकर कोई स्वतंत्र चर्चा नहीं होने देते हैं। विश्वविद्यालयों में शिक्षक पदों पर घटिया स्तर की नियुक्तियां हो रही हैं और ऐसे लोगों की भी नियुक्तियां हो रही हैं जो तयशुदा न्यूनतम योग्यता भी पूरी नहीं करते हैं। और राज्यों में छांट-छांटकर लगाए गए गवर्नर, विश्वविद्यालयों के चांसलर की अपनी हैसियत से, आरएसएस के चहेतों को विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक प्रमुखों के रूप में नियुक्त कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता के सोचे-समझे विनाश के साथ, कोई साधारण नागरिक अपने बच्चे को ऐसी किसी संस्था में क्यों भेजना चाहेगा, भले ही ऐसा करना उसकी सामर्थ्य में भी क्यों नहीं हो। दूसरे शब्दों में ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार द्वारा संचालित संस्थाएं, नव-उदारवादी सिद्धांतों के आधार पर फंडिंग की कमी ही नहीं भुगत रही हैं बल्कि गुणवत्ता के सोचे-समझे विनाश को भी भुगत रही हैं और यह फासीवादी संगठनों का योगदान है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कनन ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पीरागढ़ी एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। ([illegible])

विशेष कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का हुआ आयोजन

रामकोला, कुशीनगर।

शिव दुलारी देवी दलडपट शाही महिला पी.जी. कॉलेज रामकोला में हिंदी दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय परिसर में विविध सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख आकर्षण रहा विशेष कवि सम्मेलन। कार्यक्रम में महाविद्यालय की छात्राओं ने हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों की भूमिका निभाकर अद्भुत प्रस्तुतियाँ दीं। छात्राओं ने महादेवी वर्मा (सावित्री), सुभद्रा कुमारी चौहान (रजनी तिवारी), रामधारी सिंह दिनकर (अन्नू), हरिवंश राय बच्चन (रंजना भारती), मुंशी प्रेमचंद (निशा गुप्ता) जैसे हिंदी साहित्य के महान हस्तियों का रूप धारण कर अपने अभिनय एवं साहित्यिक प्रस्तुति से उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। इस कवि सम्मेलन के माध्यम से हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता और सम्मान का संदेश प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का एक विशेष अवसर तब आया, जब महाविद्यालय

की प्राचार्या डॉ. मनीषा सिंह ने महाविद्यालय की छात्रा शालिनी मध्देशिया को अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। शालिनी मध्देशिया ने हिंदी विषय में BA और MA की पढ़ाई पूर्ण करने के साथ-साथ UGC NET परीक्षा उत्तीर्ण की थी। डॉ. मनीषा सिंह ने इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए शालिनी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्राचार्या ने बताया कि महाविद्यालय में .ल. और छल. स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। इसके अतिरिक्त UPRTOU से सम्बंधित विशेष कोर्स भी चलाए जाते हैं, जो छात्राओं को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक कौशल प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा हमारी सांस्कृतिक धरोहर और पहचान का अहम हिस्सा है। छात्राओं को प्रेरित करते हुए प्राचार्या ने आग्रह किया कि वे हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार में सक्रिय रूप से भाग लें और इसे समृद्ध बनाएं। महाविद्यालय की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक इस आयोजन में भाग लिया और हिंदी दिवस को यादगार व प्रेरणादायक बनाया। कार्यक्रम के अंत में हिंदी भाषा की महत्ता पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया तथा सभी उपस्थित लोगों को अपनी मातृभाषा से स्नेह बनाए रखने हेतु प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के सभी प्रवक्ता गण व छात्राएं मौजूद रहीं।

भाजपा भटनी मंडल की प्रशिक्षण कार्यशाला सम्पन्न

सेवा पखवाड़ा एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को मिली जिम्मेदारी

भटनी देवरिया।

भारतीय जनता पार्टी भटनी मंडल द्वारा दिन रविवार को आदर्श चौराहा स्थित कमला बाबा मैरेज हाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं सेवा पखवाड़ा के निमित्त एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं देवरिया के पूर्व सांसद डॉ. रमापति राम त्रिपाठी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष रोहित मिश्रा ने तथा संचालन मंडल उपाध्यक्ष सत्यव्रत मिश्र ने किया। मंडल प्रभारी सचिंद्र शाही ने उपस्थित जनों का स्वागत किया। भटनी ब्लॉक/मंडल के संयोजक का दायित्व शीर्ष नेतृत्व ने पूर्व मंडल अध्यक्ष योगेश प्रजापति को दिया, जिन्होंने अपने संबोधन में कार्यक्रम की रूपरेखा व आयोजन से जुड़े बिंदुओं पर प्रकाश डाला। सेवा पखवाड़ा (17 सितंबर से 2 अक्टूबर) के कार्यक्रमों के सफल आयोजन हेतु विभिन्न जिम्मेदारियां दी गईं, जिनमें किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष शिव सरदार मिश्र, मंडल उपाध्यक्ष विश्वंभर तिवारी, अभय तिवारी, शैलेन्द्र मिश्रा, दीपक वर्मा, मंडल महामंत्री आशीष पासवान, कृष्णदत्त मिश्रा, मंडल मंत्री संजय कुमार, सत्यप्रकाश श्रीवास्तव शामिल रहे। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद डॉ. रमापति राम त्रिपाठी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और संगठन में कार्यकर्ताओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष गंगासिंह कुशवाहा, भटनी नगर पंचायत अध्यक्ष विजय गुप्ता उर्फ मुन्ना, पूर्व अध्यक्ष रमेश वर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष शेषनाथ मिश्र, अमित तिवारी, अल्पसंख्यक मोर्चा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रोशन जमीर कल्लू, वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद दीक्षित, मंडल मीडिया प्रभारी शेषनाथ कुशवाहा समेत सभी मंडल पदाधिकारी, शक्तिकेंद्र संयोजक, बूथ अध्यक्ष एवं सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

राम गुलाम राय पी.जी. कॉलेज में हिन्दी दिवस समारोह सम्पन्न

भटनी देवरिया।

राम गुलाम राय पी.जी. कॉलेज, बनकटाशिव, सलहपुर, देवरिया में उत्साहपूर्वक हिन्दी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉ. राजेश्वर शाही द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन से किया गया।

भूगोल विभाग के डॉ अनिल कुमार सिंह ने कहा कि हिन्दी सांस्कृतिक विविधता की प्रतीक और भारतीय जनमानस की भाषा है। डॉ कमलेश मिश्र ने शिक्षा व्यवस्था में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात कही। डॉ मनमोहन सिंह ने कहा कि हिन्दी मन,

वक्ताओं ने कहा—हिन्दी प्रेम, संस्कार और संस्कृति की भाषा है

प्रेम और संस्कार की भाषा है। डॉ राधा रमण मिश्र ने पुराने हिन्दी सिनेमा को हिन्दी भाषा को आगे बढ़ने में सहायक बताया।मुख्य संचालक डॉ संदीप कुमार सोनकर ने कहा कि हिन्दी हमारी संस्कृति की पहचान है, जो आधुनिकता के प्रभाव से उपेक्षित हो रही है।कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉ राजेश्वर शाही ने कहा कि हिन्दी का स्वर 'अ' से शुरू होकर 'ज्ञ' पर समाप्त होता है, जो सबको ज्ञानी बना देता है। इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी शिक्षक, कर्मचारी, छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अब्दुल हमीद ने किया। छात्राओं पायल, अस्तुति, स्वीटी सहित अन्य ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई।

भेलपुरी विक्रेता ने की आत्महत्याः 4 साल से किराए पर रह रहा था

नेबुआ नौरंगिया,कुशीनगर ।

कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के पचफेड़ा में कट्टीन के मकान में सुबह एक व्यक्तिका फंदे से लटकता शव मिला। गाँव के लोग सुबह करीब 8 बजे कोई किसी काम से उसके पास गया तो45 वर्षीय व्यक्ति को लटकता हुआ पाया। घटना कीजानकारी मिलते ही ग्राम प्रधान भीम यादव ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पंचनामा की कार्रवाई की और पोस्टमार्टमके लिए भेज दिया।स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक जो महराजगंज जिलेके परतावल इलाके के पास का रहने वाला है। मृतक गांव-गांव घूमकर भेलपुरी बेचता था। वह लगभग 4साल पहले आया और नगीना सिंह के मकान में रहने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए बिना किसी इंक्रायरी के मकान मालिक नगीना सिंह पचफेड़ा चौराहेपर बनी अपनी मकान को रहने के लिए दे दिया।

इलाके के लोग उसे भेलपुरी वाला ही कहकर बुलाते थे। इन दिनों वह बीमार भी चल रहा था। घटनास्थल से कुछ दवाइयां भी बरामद हुई।मामले पर नेबुआ नौरंगिया थानाध्यक्ष ने बताया कि व्यक्ति ने फांसी लगाई है जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रथमदृष्टया मामला सुसाइड का लग रहा है। मृतक के बारेमें पता लगाने की कोशिश की जा रही। अभी तक जोजानकारी मिली है उसके अनुसार वह महराजगंज जिलेके परतावल के आसपास का रहने वाला है।

देश को एक सूत्र में बांधने का काम करती है हिंदी- अश्वनी पांडे

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर।

क्षेत्र के किसान इंटर कॉलेज पिपरा बाजार में राष्ट्रीय सेवा योजना - नियमित कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें भाषण एवं कविता पाठ के माध्यम से छात्र छात्राओं व अध्यापकों ने हिंदी के महत्व व विशेषताओं को बताया। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्पार्चन एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ की गई। कक्षा 8 के छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य अश्विनी कुमार पांडेय ने हिंदी को राष्ट्र की अद्वितीय पहचान बताते हुए कहा कि भारतीय संविधान सभा मे 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था,उसी दिवस की स्मृति को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं।कश्मीर से कन्याकुमारी

राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन

तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक पूरे देश को एकसूत्र में बांधने का काम हिंदी भाषा ही करती आयी है। हिंदी प्रवक्ता व कवि सुनील कुमार पांडेय ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम भी है। हमें इसके प्रचार-प्रसार और दैनिक जीवन में इसके उपयोग को बढ़ाना चाहिए।साथ ही अपने कविता पाठ के द्वारा हिंदी की विशेषताओं को समझाने का प्रयास किया। डॉक्टर विष्णु प्रताप चौबे ने हिंदी साहित्य को भारतीय समाज का दर्पण और संस्कृति का संरक्षक बताते हुए इसके वर्तमान स्वरूप को और भी सबल बनाने को कहा।हिंदी आज भारत के अलावा फिजी, मॉरीशस, थाईलैंड, नेपाल, रूस में भी बहुत लोकप्रिय है।

वरिष्ठ प्रवक्ता संजय कुमार गौतम ने हिंदी को जन जन की भाषा बताते हुए कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है और अनु0 351 में इसके विकास हेतु नियम व दिशानिर्देश दिए गए हैं। कक्षा 7 व 8 की छात्राओं ने हिंदी के महान साहित्यकार व कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रसिद्ध कविता निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल गीत प्रस्तुत करके खूब प्रशंसा प्राप्त की। कार्यक्रम का संचालन एनएसएस के कार्यक्रमाधिकारी कृष्ण कुमार मिश्र ने किया। कार्यक्रम में नितिन काम्बोज, शिवेंद्र कुमार चौबे, चन्द्रभूषण पांडेय,अरूंधत्ति दुबे,रानी मिश्रा,योगेंद्र यादव,एनएसएस वालंटियर व सभी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

रूस-यूक्रेन सीमा पर फंसे हरियाणा के दो युवक: मां ने रोते हुए पीएम से लगाई गुहार, बेटे से नहीं हो रहा संपर्क

फतेहाबाद । रूस-यूक्रेन की सीमा पर फंसे दो युवकों अंकित जांगड़ा उम्र 23 साल और विजय कुमार उम्र 25 साल का परिवार के लोगों से तीन दिन से पूरी तरह से संपर्क टूट गया है। बेटे अंकित से संपर्क नहीं होने के कारण उनकी मां सुशीला का रो-रोकर बुरा हाल है।

सुशीला ने रुंधे गले से बताया कि जे सरकार म्हारी सुनाई करे तो हमारा बच्चा वापस आ जै, म्हे बहुत परेशान है। मुझे विश्वास है मोदी सरकार पै, बेटे जरूर अपने वतन लौटेंगे। गांव कुम्हारिया के अंकित जांगड़ा और विजय कुमार का तीन दिन बाद भी परिवार से संपर्क नहीं हुआ है। परिवार मोबाइल फोन पर मैसेज कर रहा है, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा है। अंकित की मां सुशीला ने बताया कि परसों बात हुई, फिर कोई बात नहीं हुई। वीरवार रात को अंकित ने अपने भाई रघुबीर के मोबाइल फोन पर वॉइस मैसेज भेजा था कि बचा लो सुबह 5 बजे युद्ध क्षेत्र में ले जाएंगे। वहीं, विजय ने अपने भाई सुनील के पास मैसेज किया था। हालांकि इससे

पहले रूस में दोनों के सोशल मीडिया एप डिलीट करवा दी गई थी। दोनों वीडियो कॉल के जरिये परिवार से संपर्क कर रहे थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। वीडियो में दोनों सेना की वर्दी में नजर आ रहे थे।

पांच लाख रुपये कर्ज लेकर भेजा था विदेश

अंकित के भाई रघुबीर ने बताया कि उनके पिता राजमिस्त्री हैं। पिता ने पांच लाख रुपये कर्ज लेकर भाई को विदेश भेजा था। उम्मीद थी कि बेटा आर्थिक मदद करेगा, लेकिन अब मकान का निर्माण अधूरा है। विजय के भाई सुनील का कहना है कि गांव के कुछ लड़के पहले भी रूस जा चुके हैं। विजय सीएससी चलाता था और जून में ही रूस गया था, लेकिन वहां जाकर वह फंस गया है।

अब सरकार के हाथ में है सब कुछ

रघुबीर ने कहा भाई अंकित का अंतिम मैसेज यही आया था कि ये लोग हमें आगे लेकर जा रहे हैं। सरकार से प्रार्थना है कि मदद करें। सीएम सैनी से दो बार मिल चुके हैं। सीएम को कहा है कि वह स्टडी वीजा पर गए हैं, डंकी रूट के जरिये नहीं। उनके साथ जो हालात बने हैं वह उन्हें ही पता है। केंद्र और प्रदेश सरकार के हाथ में सब कुछ है। बच्चों की गलती है कि वे लालच में आ गए। पीएम मोदी से प्रार्थना है कि वे बच्चों को वहां से निकलवाएं। मदद के लिए वे विदेश मंत्रालय, की एंबेसी भी जा चुके हैं।

युवक की पीट-पीटकर हत्या करने के चार आरोपी गिरफ्तार

पानीपत। रैरकला गांव के खेतों में बंधक बनाकर मोहित (21) की पीट पीटकर हत्या करने के चार आरोपियों को थाना सदर पुलिस ने शनिवार शाम को रिफाइनरी लोहा पुल के पास से गिरफ्तार किया।

आरोपियों की पहचान हरी नगर हाल कच्चा कैंप दीवान नगर निवासी सुरेश, बत्तरा कालोनी निवासी सौरभ उर्फ धोला, शक्तिनगर निवासी जतिन उर्फ चीता व ईदगाह कॉलोनी निवासी राहुल उर्फ काला के रूप में हुई है। पूछताछ में चारों आरोपियों ने फरार अपने अन्य कई साथी आरोपियों के साथ मिलकर उक्त वारदात को अंजाम देने बारे स्वीकारा। उप पुलिस अधीक्षक श्री राजबीर सिंह ने बताया कि थाना सदर में पसीना कला गांव निवासी अजय पुत्र मनोज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बहन खीना व बुआ राजरानी गांव रैरकला में शादीशुदा है। 8 सितंबर को उसका बेटा मोहित (21) गांव निवासी आशीष को अपने साथ लेकर बहन व बुआ से मिलने के लिए रैरकला गांव गया था। 10 सितंबर को बेटे मोहित ने उसको बताया कि उसे दस्त लग गए थे। वह रात करीब 9 बजे बूआ व बहन को दस्त की बात बताकर आशीष के साथ बाहर घूमने गया था। तभी एक कार व कई बाइकों पर 20/25 युवक आए। उनके हाथों में बर्फ तोड़ने वाले सूए व लाठी, डंडें थे। युवकों ने उन दोनों को रोककर जातिसूचक शब्द कहे और घूमने का कारण पूछा। हरि नगर निवासी ठेकेदार सुरेश, सुमित व विक्की, बतरा कॉलोनी निवासो रिंकू व सौरभ, ईदगाह कॉलोनी निवासी राहुल, शक्ति नगर निवासी जतिन और राजबीर व उसका लड़का उन दोनों को जातिसूचक गाली गलौच करते हुए अपनी कार में डालकर खेतों मे एक तालाब के पास ले गए। वहा दोनों के कपड़े निकाल दिए और रस्सी से बांध दिया। उन पर लाठी डंडों, सुए व अन्य हथियारों से

हमला किया। बार बार जाति सूचक गालिया देते रहे। आरोपियों ने दोनों को बेरहमी से पीटा। बेटे मोहित ने 11 सितंबर को पीजीआई खानपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आशीष का पानीपत के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। थाना सदर में अजय की शिकायत पर बीएनएस की धारा 191(3), 190, 126(2), 115(2), 140(1), 103(1) व एससी एसटी एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी। उप पुलिस अधीक्षक श्री राजबीर सिंह ने बताया कि थाना सदर पुलिस ने शनिवार शाम चार आरोपियों हरी नगर हाल कच्चा कैंप दीवान नगर निवासी सुरेश, बत्तरा कालोनी निवासी सौरभ उर्फ धोला, शक्तिनगर निवासी जतिन उर्फ चीता व ईदगाह कॉलोनी निवासी राहुल उर्फ काला को रिफाइनरी लोहा पुल के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने अपने फरार अन्य कई साथी आरोपियों के साथ मिलकर उक्त वारदात को अंजाम देने बारे स्वीकारा। पूछताछ में आरोपी सुरेश ने पुलिस को बताया उसने मच्छली पालन के लिए रैरकला गांव में तालाब को ठेके पर लिया हुआ है। तालाब से मच्छली चोरी हो जाती थी। 8 सितंबर की देर रात वह उसका बेटा विक्रम, भांजा, सुमित, रिंकू सौरभ व राहुल, जतिन व बेटे के भांजे सुमित के अन्य तीन चार दोस्तों के साथ अपनी कार व अन्य कई बाइकों पर सवार होकर तालाब की निगरानी के लिए रैरकला गांव गए थे। वहा गांव की और से दो युवक खेतों की और जाते दिखे। मच्छली चोरी के शक में वह दोनों युवकों को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर तालाब के पास खेतों में ले गए। वहा रस्सी से बांधकर दोनों को लाठी, डंडों से पीटा के साथ ही मच्छली निकालने वाले काटे से चोट मारी। वारदात को छुपाने के लिए उसने डॉयल 112 पर काल कर सूचना दी कि उसने मच्छली चोरी करने वाले दो चोर पकड़े है। और दोनों युवकों की रस्सी खोलकर वह सभी मौके से फरार हो गए थे। उप पुलिस अधीक्षक श्री राजबीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने चारों आरोपियों को रविवार को माननीय न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ करने के साथ ही वारदात में प्रयुक्त लाठी, डंडें, बाइक व कार बरामद करने व वारदात में शामिल फरार इनके साथी आरोपियों के ठिकानों का पता लगा पकड़ने का प्रयास करेगी।

हिरासत में मौतें : पुलिस थानों में सीसीटीवी नहीं चलने पर अदालत ने लिया स्वतः संज्ञान; सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

नई दिल्ली। देशभर के पुलिस थानों में काम न कर रहे या गायब सीसीटीवी कैमरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। इसके तहत एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मामले में दायर स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ करेगी। इस याचिका में पुलिस हिरासत में हो रही मौतों और मानवाधिकार उल्लंघनों पर चिंता जताई गई है। कोर्ट ने बीते चार सितंबर को एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि इस साल के पहले सात से आठ महीनों में पुलिस हिरासत में 11 मौतें हुई हैं। ऐसे में सीसीटीवी कैमरों की गैर-मौजूदगी गंभीर मुद्दा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद बात अगर पिछले फैसले की करें तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि मानवाधिकार हनन को रोका जा सके। इसके बाद दिसंबर 2020 में कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीबीआई, ईडी और एनआईए जैसे जांच एजेंसियों के दफ्तरों में भी सीसीटीवी और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का निर्देश दिया था। बता दें कि कोर्ट के पिछले आदेश के अनुसार हर पुलिस स्टेशन के प्रवेश और निकासी द्वार, मुख्य गेट, लॉकअप, कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन और लॉकअप के बाहर के हिस्से में सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी है। इसके अलावा कि कैमरों में नाइट विजन (रात में दिखने की क्षमता) और ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों होनी चाहिए। इसके साथ ही रिकॉर्डिंग कम से कम एक साल तक स्टोर करने की सुविधा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मामले में स्वतः संज्ञान जनहित याचिका दर्ज की है। गौरतलब है कि जिस मीडिया रिपोर्ट को कोर्ट ने आधार बनाया है उसमें बताया गया कि देश के कई पुलिस थानों में अभी भी सीसीटीवी कैमरे या तो नहीं लगे हैं या फिर काम नहीं कर रहे हैं, जिससे पुलिस हिरासत में हो रही मौतों और अमानवीय व्यवहार पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट अब इस गंभीर मुद्दे पर खुद निगरानी करते हुए सुनवाई करेगा।

दिल्ली एक मिनी भारत है, आप लोग न हों तो..., जनता के लिए सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान

नई दिल्ली। (वेबवार्ता) दिल्ली के एम्स में आयोजित ओनम पोनोनम 2025 कार्यक्रम में 14 सितंबर को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सच में एक मिनी भारत है. उन्होंने बताया कि यहां जम्मू-कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक, हर राज्य के लाखों लोग रहते हैं. सीएम ने कहा कि दिल्ली को उन्होंने अपनी एक्सटेंडेड फैमिली की तरह माना है और हर व्यक्ति का इस शहर पर बराबर अधिकार है. सीएम गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में रहने वाले लोग न सिर्फ अपने सपनों, भविष्य और करियर से यहां जुड़े हैं बल्कि यह शहर उनके परिवार का हिस्सा भी है. उन्होंने कहा कि अगर हर राय के लोग दिल्ली में न होते तो यहां की रफ्तार रुक जाती. मुख्यमंत्री ने इस विविधता को दिल्ली की ताकत बताया और कहा कि सभी रायों के नागरिक मिलकर ही दिल्ली को आगे बढ़ा रहे हैं. रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली की पहचान इसके बहुरंगी त्योहार और सांस्कृतिक आयोजनों से है. पीटीआई के अनुसार, उन्होंने ओडिशा की जगन्नाथ पूजा का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने हाल ही में जगन्नाथ यात्रा में भाग लिया. इसके अलावा उत्तराखंड, महाराष्ट्र और अन्य रायों के कार्यक्रमों जैसे गणपति उत्सव और नवरात्रि के डांडिया की भी चर्चा की. सीएम के अनुसार, इन त्योहारों से दिल्ली की रौनक बढ़ती है और पूरे भारत की झलक एक ही शहर में देखने को मिलती है. कार्यक्रम में ओनम पर्व की बधाई देते हुए सीएम गुप्ता ने कहा कि यह त्योहार 10 दिनों तक पूरे देश में खुशियां और एकता का संदेश देता है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में आज दो महोत्सवों का माहौल है और यह हम सबके लिए गर्व और खुशी का अवसर है. मुख्यमंत्री ने अंत में यह भी कहा कि दिल्ली की यही विशेषता है कि यहां हर संस्कृति और हर त्योहार को समान उत्साह से मनाया जाता है, जिससे यह सचमुच 'मिनी भारत' की पहचान पाती है.

भिखारियों के आश्रयगृह में सुनिश्चित हो गरिमापूर्ण जीवन, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिया निर्देश

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भिखारियों के लिए राय संचालित आश्रयगृह (बेगर्स होम) कोई इच्छा से दिया गया दान नहीं नहीं है, बल्कि यह एक सांविधानिक जिम्मेदारी है। शीर्ष कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन आश्रयगृहों में गरिमापूर्ण जीवन की स्थितियां लगातार सुनिश्चित की जानी चाहिए। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि सभी राय और केंद्र शासित प्रदेश अपने नियंत्रण में भिक्षावृत्ति करने वाले के लिए बने आश्रयगृहों और इसी तरह के संस्थानों में सुधारों को लागू करें, ताकि समाज के इस सबसे कमजोर वर्ग के लिए गरिमा के साथ जीवन जीने का सांविधानिक अधिकार सही मायने में सुनिश्चित हो सके। बेंच ने कहा कि ऐसे आश्रयगृहों में मानवीय परिस्थितियां बनाए रखने में विफलता केवल प्रशासन की लापरवाही नहीं है, बल्कि यह जीवन के साथ गरिमा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि गरीब और बेसहारा लोगों के प्रति राय की जिम्मेदारी सकारात्मक होनी चाहिए। भिखारियों का आश्रयगृह राय संचालित एक सांविधानिक ट्रस्ट है, न कि किसी की इच्छा पर आधारित दया। इसके संचालन में सांविधानिक नैतिकता यानी स्वतंत्रता, निजता और गरिमापूर्ण जीवन की शर्तें प्रतिबिंबित होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि भिखारियों के हर आश्रयगृह में भर्ती होने वाले व्यक्ति का चौबीस घंटे के भीतर किसी योग्य डॉक्टर से अनिवार्य रूप से मेडिकल परीक्षण किया जाना चाहिए। सभी की हर महीने स्वास्थ्य जांच हो और संक्रामक व पानी से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम, पहचान और नियंत्रण के लिए एक विशेष व्यवस्था बनाई जाए। इसके साथ ही सभी रायों और केंद्र शासित प्रदेशों को भिखारियों के आश्रयगृहों में स्वच्छता और साफ-सफाई के न्यूनतम मानक तय करने का निर्देश दिया। इसमें स्वच्छ पानी की उपलब्धता, शौचालय, उचित नाली व्यवस्था और कीट व मच्छर नियंत्रण जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। शीर्ष कोर्ट ने यह निर्देश तब दिया, जब दिल्ली के सीलमपुर में भिखारियों के आश्रयस्थल में पीने और भोजन बनाने के पानी में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की वजह से हैजा और गैस्ट्रोएंटेराइटिस का प्रकोप फैला। कोर्ट ने कहा कि सभी रायों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर दो साल में भिखारियों के आश्रयगृहों का स्वतंत्र और तीसरे पक्ष से निष्पक्ष ऑडिट कराना होगा।

.तो खून और खेल साथ-साथ कैसे, सांसद संजय सिंह ने किया भारत-पाकिस्तान मैच का विरोध

नई दिल्ली। एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार विरोध कर रहे हैं. इस क्रम में आम आदमी पार्टी के नेता और रायसभा सांसद संजय सिंह ने इस मैच को लेकर आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार को घेरा है. उन्होंने सवाल उठाया कि पीएम मोदी का बयान है कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते तो फिर खून और खेल साथ-साथ कैसे चल सकते हैं. सांसद संजय सिंह ने कहा, पहलगाम में हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया. भारत की सरकार ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर घटना को अंजाम दिया. उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए. आम नागरिक मारे गए, एक एडीसी शहीद हुए. आप मुझे बताइए कि जिस पाकिस्तान से आपकी लड़ाई हो रही है, उसके साथ मैच कैसे खेल सकते हैं? उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा, आपने खुद कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है. ये मेरा बयान नहीं है. ये भारत की सरकार का बयान है. खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, ये मेरा बयान नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है. टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता है, ये मेरा बयान नहीं है बल्कि भारत के प्रधानमंत्री का बयान है. तो खून और खेल एक साथ कैसे चल सकता है? क्योंकि उसमें आपके बेटों का धंधा जुड़ा हुआ है, हजारों करोड़ रुपये की कमाई जुड़ी हुई है. बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के खिलाफ शनिवार (13 सितंबर) को प्रदर्शन भी किया था. इसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एशिया कप में रविवार को भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच की अनुमति देने के फैसले पर सवाल उठाया. उन्होंने पूछा, "प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान के साथ मैच करवाने की आखिर क्या जरूरत है? वहीं, आप की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को 'अपमानित' करने का आरोप लगाया. गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान के साथ क्रिकेट संबंधों के बहिष्कार की मांग की जा रही है.

झगड़े में बीच-बचाव करने आए युवक की चाकू घोंपकर हत्या, 6 नाबालिग बदमाश गिरफ्तार

बाहरी दिल्ली। मंगोलपुरी में किराने की दुकान पर कल रात झगड़े के बाद हुई चाकूबाजी व मारपीट में दुकानदार समेत तीन लोग घायल हो गए। बाद में इलाज के दौरान घायलों में से एक युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक युवक दुकान पर कुछ सामान लेने आया था और झगड़े में बीच-बचाव के दौरान हमलावरों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में दुकानदार व उसका दोस्त भी घायल हो गए, जहां मरहम-पट्टी के बाद उन्हें छुट्टी मिल गई। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए शनिवार को हत्या के आरोप में छह नाबालिग को पकड़ लिया है। बाहरी जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कल रात मंगोलपुरी थाना पुलिस को जे-ब्लाक में चाकूबाजी की घटना के संबंध में पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। इसके बाद पुलिस संजय गांधी

अस्पताल पहुंची, जहां पता चला कि मंगोलपुरी निवासी 32 वर्षीय अरुण नामक व्यक्ति के पैर में चाकू से गंभीर चोट लगी है। उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अरुण मंगोलपुरी में किराए पर रहता था। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह मंगोलपुरी में एक किराना दुकान चलाता है, जहां घटना के समय अरुण भी मौजूद था। इसी दौरान उसका परिचित पंकज दुकान पर आया, तभी 5-6 लड़कों ने पंकज से झगड़ा किया। जब शिकायतकर्ता और अरुण ने बीच-बचाव किया तो लड़कों ने उन पर हमला कर दिया। इस दौरान एक नाबालिग ने पीड़ित के पैर में चाकू घोंप दिया। सूचना मिलने के बाद आलाधिकारियों सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और क्राइम टीम को भी मौके पर बुलाया गया। जिसने मौके से सबूतों को इकट्ठा किए। चाकूबाजी की यह घटना पास में ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में हाथों में चाकू लेकर कुछ लड़के हमला करते दिखाई दे रहे हैं। बाद में दुकानदार सचिन ने बताया कि पंकज के साथ हुए झगड़े में वे और अरुण बीच-बचाव करने गए थे। हमले में तीनों को चोट लगीं। मुझे और पंकज को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी मिल गई। अरुण को सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी पूनम ने बताया कि उनके पति अरुण दूध लेने के दुकान पर गए थे और इसी दौरान कुछ लोगों ने अरुण व दुकानदार पर हमला बोल दिया।